

12
2016

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

110
7

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०



निगरानी पंचायत प्रकरण सं० 12/16

रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्रहामण निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1.मंजूदेवी पत्नी श्री कलवन्त जाति जाट निवासी चक 36 पी एस हाल सरपंच ग्राम पंचायत खांटा, प० सं० रायसिंहनगर।
- 2.महेन्द्र वर्मा पुत्र नाम ना मालूम जाति वर्मा हाल ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांटा, प० सं० रायसिंहनगर।
- 3.विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर।
- 4.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

उपस्थित :-

- 1 श्री रामचन्द्र, निगरानीकर्ता स्वयं
2. राजकीय अधिवक्ता


आदेश

दिनांक : 26.4.17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत खांटा, पंचायत समिति रायसिंहनगर के अन्तर्गत गाँव खांटा की आबादी भूमि का खाता सं० 1 असहायश आबादी (खसरा सं० 193 व 229), खाता सं० 3 गली (खसरा सं० 214 व 224), 4 गुवाड़ (खसरा सं० 45) 5 जगात चौकी (खसरा सं० 53), खाता सं० 6 पायतन जोहड़ (खसरा सं० 10,48 व 50), खाता सं० 7 सरकारी दुकान (खसरा सं० 207,240 व 251) जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि की श्रेणी में आती है, को अप्रार्थीगण के पूर्ववर्ती द्वारा अपने हितबद्ध व्यक्तियों को नियम विरुद्ध आवंटित करने एवं इस बाबत राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 व पूर्ववर्ती अधिनियमों एवं नियमों के विरुद्ध आवंटित कर दिया है, जिसके तहत खाता सं० 1 ससहायश आबादी के रूप में दर्ज है। नियमानुसार उक्त आबादी भूमि के पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं। निआश्रित व्यक्ति मात्र स्वयं रहने का पात्र होता है, पट्टे

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जारी करने की स्थिति में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है। अप्रार्थीगण ने खसरा सं० १९३ में ओमप्रकाश, भानूराम, रघुवीर,आईदान पुत्र श्री बालूराम, धरराज पुत्र श्री पुरखाराम, कृष्ण राम पुत्र खेताराम, जगदीश पुत्र खेताराम, हर लाल पुत्र खेताराम, नाथी पत्नी बीरबल, श्रवण पुत्र कानाराम, कृष्ण पुत्र कानाराम नाई, रामकुमार पुत्र खेताराम, पुरखाराम पुत्र नानकराम आदि को आवंटित कर दिया। इनमें से मात्र एक दो व्यक्ति असहाय की श्रेणी में आते हैं, शेष साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं जो निःशुल्क आवंटन की पात्रता नहीं रखते हैं। इसी प्रकार, खसरा सं० १९३ में २१४ एवं २२४ सार्वजनिक गली हेतु आरक्षित भूमि के रूप में दर्शायी गई है, जिसका आवंटन रिहायशी प्लाट के रूप में ओमप्रकाश, मनफूल, हजारी लाल, आसाराम, चेताराम, जगमाल, हरलाल पुत्र सुल्तान आदि को पट्टा जारी कर दिया है। खसरा सं० २२२, २२३ आरक्षित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत माफी स्कूल के रूप में आबादी भूमि में चिन्हित भूमि है, को हर लाल पुत्र सुल्तान के नाम से पट्टा जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार खसरा सं० २२९ में असहायश आबादी के रूप में रामकुमार पुत्र सदासुख पट्टा सं० ३५, महेन्द्र पुत्र गोविन्द, ओमप्रकाश पुत्र नानकराम, नन्दराम, गाविन्दराम के नाम से पट्टे जारी कर दिये गये हैं। पूर्ववर्ती ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव विजय भूषण पाहवा द्वारा वर्ष २००१ से सीमादेवी पत्नी रामस्वरूप को पट्टा सं० ४०२५, साहबराम, शेराराम, रणजीत पुत्र गोर्वधन पट्टा सं० १४, भागीरथ पट्टा सं० ४०, ४२, विनोद कुमार, मोनिका, नेतराम, सुलोचना, पट्टा सं० ४०२३, ताराचन्द्र पुत्र नंदराम, सजनादेवी पत्नी श्री दलीप, शारदा, सुभाष, ईमीलाल को पट्टा सं० ७, १ व २ नियमविरुद्ध जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार बाहर के रहने वाले लोगों को भी गाँव खांटा का निवासी बता कर गलत पट्टे उनके नाम से जारी कर दिये हैं। इसी प्रकार, राम प्रताप, मदन लाल पुत्र नानूराम, प्रेमसिंह पुत्र सदासुख, तुलसी पत्नी तोलाराम, देवी लाल पुत्र चेताराम, उदाराम पुत्र भानीराम, भूपसिंह पुत्र सदासुख जो कि पूर्ववर्ती सरपंच हर लाल व सदासुख के निजी रिश्तेदार हैं जो कि अबूब शहर हरियाणा वर्तमान में पंजाब, भादरा, खैरुवाला, मटीली के निवासीगण हैं, उनको नियमविरुद्ध पट्टे जारी किये गये हैं। खाता सं० ६ जोहड़ पायतन (जोहड़ की पाल) खसरा सं० १०, ४८,५०, खाता सं० ४ गुवाड़, खसरा सं० ४५, खाता सं० ०५ जगात चौकी, खसरा सं० ५३ व खाता सं० ०७, सरकारी दुकान, खसरा सं० २०७,२४०,२५१ के रूप में सरकारी सम्पत्ति के रूप में रिकार्ड में दर्ज है, उसका भी आवंटन व्यक्ति विशेष को कर दिया गया है। आवंटन में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। धारा १०० के अन्तर्गत निरीक्षण एवं जाँच नहीं करवाई गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण एवं उनके पद


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पूर्ववर्ती व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध कार्य को जनहित में निरस्त फरमाई जाने की कार्यवाही को अमल में लाई जा सके।

निगरानीकर्ता की ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। निगरानीकर्ता स्वयं ने एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस की, जो सुनी गई।

निगरानीकर्ता ने अपनी बहस बताया है कि ग्राम पंचायत द्वारा बाहर के व्यक्तियों को नियमविरुद्ध पट्टे जारी कर दिये गये हैं, जो पात्र नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों को जारी नियमविरुद्ध पट्टे निरस्त किये जाकर पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जावें।


राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकर्ता ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह निगरानी की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि प्रार्थना पत्र में नियमविरुद्ध आवंटन के खिलाफ शिकायत की गई है जबकि निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के किसी विशिष्ट आदेश/कार्यवाही/प्रस्ताव/पट्टे को कानूनी बिन्दू पर चुनौति दी जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। हस्तगत निगरानी में ऐसे किसी विशिष्ट आदेश/कार्यवाही/प्रस्ताव/पट्टे को चुनौति नहीं दी गई है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निगरानी की परिधि में नहीं होने से निगरानी संधारण योग्य नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है और न ही निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के किसी विशिष्ट आदेश/कार्यवाही/प्रस्ताव/पट्टे को चुनौति दी गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह ग्राम पंचायत द्वारा किये गये आवंटन के संबंध में शिकायत है। ऐसी शिकायत के उपरांत ही यह निर्धारित हो सकता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा किया गया आवंटन विधिविरुद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निगरानी की परिधि में न होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के अन्तर्गत पोषणीय न होने से खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में ग्राम पंचायत के रेकार्ड की जाँच कर, यदि


अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2016

जॉचोपरांत नियमविरुद्ध पट्टे जारी होने पाये जाते हैं तो प्रत्येक आवंटी के विरुद्ध पृथक-2 निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत को भी भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24.4.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/17
(करतारसिंह पूनिया)

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर